बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 55

जेट के सबक

बीते बुधवार को देर रात 12.30 बजे जब जेट एयरवेज (एक समय देश की दूसरी सबसे बड़ी निजी विमानन कंपनी) की अंतिम उड़ान मुंबई में उतरी तो विमान चालक ने अपने संदेश में कहा, 'हम आशा करते हैं कि हम दोबारा जल्द उड़ान भरेंगे। जब भी ऐसा हो, आप हमारी सेवा लें।' 25 वर्ष पहले शुरू हुई जेट एयरवेज के लिए यह एक मार्मिक क्षण था लेकिन सेवाओं का अनिश्चित कालीन निलंबन कतई चौंकाने वाली बात नहीं थी क्योंकि वर्ष की शुरुआत 119 विमानों से करने वाली कंपनी के पास अब बमुश्किल पांच विमान परिचालन के लिए बचे थे। कंपनी पर 8,400 करोड़ रुपये का कर्ज है और मार्च में बनी सहमति के विपरीत कंपनी को कर्जदाताओं से परिचालन के लिए जरूरी ऋण नहीं मिल सका। विमानन कंपनी की हालत निश्चित रूप से बेहद खराब है। बड़े हवाई अड्डों पर उसका बेहतरीन प्रस्थान समय अब या तो दूसरी विमानन सेवाओं को आवंटित हो चुका है या जल्दी ही ऐसा हो जाएगा। 25 मार्च को हिस्सेदारी बेचने और प्राथमिकता वाली फंडिंग की समझौता योजना की घोषणा करने के बाद जेट के कर्जदाताओं का रुख ठंडा क्यों पड़ गया, इसे समझना कठिन नहीं है। पहला, कंपनी की नकदी आवक पर बहुत बुरा असर पड़ा था और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को निरस्त कर दिया जो फंसी परिसंपत्तियों के निपटारे से संबंधित था। निस्तारण योजना उसी सर्कुलर के आधार पर बनी थी। जांच एजेसियों का निशाना बनने की आशंका ने भी बैंकरों का मानस बदलने में भूमिका निभाई होगी। विमानन कंपनी ने 400 करोड़ रुपये की घटी हुई राशि की मांग की, वह भी अव्यवहार्य विकल्प था क्योंकि अधिकांश फंड वेतन और बकाया भुगतान के लिए मांगे गए थे।

बैंकों ने कंपनी के प्रवर्तक नरेश गोयल को लंबे समय तक रियायत दी, हालांकि जेट एक ऐसे भंवर में उलझ गई थी जिसका दूर-दूर तक कोई अंत नहीं नजर आ रहा था। वर्ष 2018 के अंत में जेट के देनदारी चूकने के पहले से कुप्रबंधन के संकेत नजर आने लगे थे। विमानन कंपनी निरंतर घाटे और नकदी की तंगी के चलते अपना नियंत्रण गंवा रही थी और जेट के अंकेक्षकों ने भी गत वर्ष अगस्त में उसके बचने को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद भी बैंकों ने गोयल को स्ट्रैटेजिक निवेशकों के माध्यम से कंपनी को बचाने पर मजबूर नहीं किया। बल्कि उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि वे अपने ऋण को इक्विटी में बदल सकते हैं। यह बात अलग है कि अतीत में ऐसी कोशिशों का हश्र अच्छा नहीं रहा था। बैंकों ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालया संहिता का मार्ग अपनाने से भी इनकार कर दिया जबकि वह ऐसी ही स्थितियों के लिए बना है।

बैंकों ने गोयल को इतने लंबे अरसे तक रियायत क्यों दी, इसकी वजह ज्ञात नहीं है लेकिन ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि जेट के प्रवर्तक के कई रसूखदार मित्र थे। राजनीतिक शक्तियों को नाराज करने के डर ने भी भूमिका निभाई होगी। शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि इससे कितने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आएगी और हवाई किराये में कितना इजाफा होगा। हालांकि यह कहना होगा कि सरकार परिदृश्य से बाहर रही और उसने संकट हल करने का काम बैंकरों और विमानन कंपनी पर छोड़ दिया था। उसने एयरपोर्ट स्लॉट को अस्थायी तौर पर अन्य कंपनियों को देकर भी उथलपुथल को कम किया। फिलहाल जेट के बचने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता है। निवेशक जुटाना भी आसान नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कुछ उड़ान अधिकारों तथा लैंडिंग और पार्किंग के कुछ अधिकारों के सिवा ज्यादा कुछ है नहीं। उसकी ब्रांड वैल्यू भी तेजी से घट रही है। जेट की पूरी कहानी में अहम सबक यही है कि किसी प्रवर्तक को संस्थान से बड़ा नहीं समझना चाहिए।

बिनय सिन्हा

अंधराष्ट्रवाद और मोदी की कोशिश

मोदी-शाह की भाजपा ने अतीत के खतरों और शत्रु को नए सिरे से खड़ा किया है और एक डराने वाले अंधराष्ट्रवाद को जन्म दिया है। यह बांटने वाला तरीका है। इतिहास बताता है कि इसका अंत कभी सुखद नहीं होता।

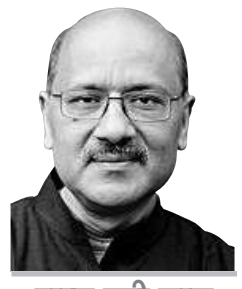

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

हिंदी मीडिया की अपनी स्वाभाविक छानबीन के दौरान मैं अतीत के एक गीत पर ठहर सा गया। इस गीत में कवि प्रदीप ने देश के भीतर के गद्दारों से सावधान रहने की बात कही थी। राजेंद्र कुमार अभिनीत और मन्ना डे के गाए इस गीत में उन्होंने कहा था, 'झांक रहे हैं अपने दुश्मन, अपनी ही दीवारों से/संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से' वह आगे लिखते हैं कि 'होशियार तुमको अपने कश्मीर की रक्षा करनी है।'

यह गीत उन्होंने महेश कौल की फिल्म तलाक के लिए लिखा था। सन 1958 में रिलीज हुई यह फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नामित हुई थी। परंतु हिंदी प्रदेश में होने वाली चर्चाओं में यह बात दोबारा क्यों उभर रही है?

आपको ऐसे संदर्भ भी मिलेंगे कि नेहरू को यह गीत बहुत नापसंद था क्योंकि इसमें कुछ भारतीयों को दुश्मन बताया गया था। इसलिए उन्होंने इसे प्रतिबंधित किया था। यह भी कि सन 1965 के युद्ध के वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने यह प्रतिबंध हटा लिया। ताजा दलील यह है कि एक ओर शत्रु दरवाजे पर खड़ा है और दूसरी ओर हमारे घरों में गद्दार छिपे हुए हैं। तथ्यों की तो बात ही छोड़ दें।

इन 60 वर्षों में, ढाई युद्धों में जीत हासिल करने, पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटने और 2.7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के बाद शायद आपको लगा होगा कि देश बहुत सुरक्षित है, समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में यह आशावाद जाग सकता है कि हम अतीत के मोह से मुक्त हो सकें।

परंतु उत्तर और दक्षिण में देश के बड़े हिस्से की यात्रा करने के बाद मैं पूरी विनम्रता से यह कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसका ठीक विपरीत हासिल कर पाए हैं। ऐसे समय में जबकि भारत को आंतरिक और बाहरी स्तर पर सर्वाधिक सुरक्षित महसूस करना चाहिए था, तब वे मतदाताओं के एक बड़े तबके को यह यकीन दिलाने में कामयाब रहे हैं कि अतीत के खतरे लौट आए हैं। इनमें बड़ी तादाद उन युवाओं की है जो व्हाट्सऐप से इतिहास की शिक्षा लेते हैं और यह मानते हैं कि भारत 2014 में अंधकार युग से बाहर आया। ऐसे में ऐसे मजबूत, आक्रामक और निर्भय नेता के अलावा आप किस पर यकीन करेंगे जो बिना पुनर्विचार किए कमांडो को सर्जिकल स्ट्राइक पर भेज देता हो या दुश्मन के क्षेत्र में विमानों से बमबारी करता हो?

अर्थव्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर इतने खराब हालात और संकट की स्थिति को प्रोपगंडा के जरिए दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। हमें अनुमान था कि मोदी और शाह इस चुनाव को 'देश खतरे में है' के नारे के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के चुनाव में बदल देंगे। हम कह सकते हैं कि वे इसमें सफल रहे।

किसी चुनाव को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के चुनाव में बदलने की तीन पूर्व शर्त हैं। पहला, राष्ट्रीय हितों को आक्रामक और उन्मादी तरीके से नए सिरे से प्रस्तुत करना। दूसरा, एक मजबूत शत्रु हो जिससे सच्चे राष्ट्रवादी नफरत करें और आशंकित रहें। सबसे महत्त्वपूर्ण बात, उस दुश्मन से सांठगांठ करने वाले और सहानुभूति रखने वाले देश में मौजूद हों केवल तभी आप उसके खिलाफ वोट मांग सकेंगे और नैतिक या राजनीतिक रूप से कोई विरोध नहीं कर सकेगा। इसे केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कहना कम समझ की बात होगी। यह काफी प्रभावी और मारक है।

राष्ट्रीय हित की ऐसी लोकप्रिय अवधारणा विकसित करने के लिए पहचान की तीव्र परिभाषा विकसित करनी होती है। अमेरिकी नीतिकार और हॉवर्ड के प्रोफेसर जोसेफ नाइ जूनियर ने फॉरेन पॉलिसी पत्रिका में लिखा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा फिसलन भरी है और इसका उपयोग विदेश नीति की व्याख्या करने में भी किया जाता है और उसे तय करने में भी। आगे वह सैमुएल हटिंगटन को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि बिना राष्ट्रीय पहचान की सुरक्षित समझ के राष्ट्रीय हित को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।

आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। हिंदू की पहचान ही भारतीय राष्ट्रवाद का मूल है। जो हिंदुओं के लिए बेहतर है, वही राष्ट्र के लिए भी बेहतर है। हो सकता है कि इसका उलटा भी सच हो। अगर ऐसा नहीं है तो इसे सुधारना होगा। गैर हिंदुओं की बात करें तो उनको भी ऐसा ही लाभ मिलेगा। परंतु अगर वे शिकायत करते हैं या असंतुष्ट रहते हैं तो वे भी घायल दिल वाले उदारवादियों, सवाल करने वाले पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शहरी नक्सल आदि की गद्दारों की सूची में शामिल हो जाएंगे। अब जरा कवि प्रदीप की उस चेतावनी को याद कर लें जो उन्होंने घर में छिपे गद्दारों के बारे में दी थी।

मोदी और शाह ने यह अभियान इसी प्रकार तैयार किया है। विपक्ष न्याय, राफेल, धर्मनिरपेक्षता, समता आदि के साथ एक अलग खेल खेल रहा है। यह वैसा ही है जैसे एक पक्ष फौजी धुन पर आगे बढ़ रहा है जबकि दूसरा तानपुरे पर आलाप ले रहा है। वे तमाम विचार भी सही हैं लेकिन सच यही है कि अगर देश नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। चूंकि ऐसे खतरे आसन्न हैं तो आप देश किसके हाथों में सौंपना चाहेंगे? एक निर्णायक और मजबूत नेता के या एक 'पप्पू' के?

देश में कोई सर्वविजेता राष्ट्रवादी लहर नहीं है लेकिन ऐसा माहौल तो है कि आर्थिक निराशा और असंतोष की काट की जा सके। देश के दूरदराज इलाकों में आपको ऐसे युवा, बेरोजगार और नाउम्मीद लोग मिलते हैं जो कहते हैं उनके पास काम नहीं है और वे परेशान हो रहे हैं लेकिन वे देश के लिए थोड़ा कष्ट सहने को तैयार हैं। हमें भले ही यह सब बेवकूफाना और बेतुका लगे लेकिन इससे हकीकत नहीं बदल सकती।

दूसरा कारक है पहचान। यह लहर आबादी के एक बड़े हिस्से में कमजोर या नदारद है। यह आबादी का वह हिस्सा है जिसकी राजनीतिक पहचान हिंदू धर्म से कहीं अधिक मजबूत है। यह जाति भी हो सकती है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में वोक्कालिगा और उत्तर प्रदेश में यादव तथा देश के लगभग हर हिस्से में दलित। यह भाषा और जातीयता भी हो सकती है मसलन तमिल और तेलुगू। यह धर्म के आधार पर भी हो सकता है मसलन मुस्लिम और ईसाई। जहां भी ऐसे कुछ कारक मिलते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, तब यह स्थिति निर्मित हो सकती है।

यही कारण है कि सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को हुआ है। कई अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह उसके पास वैकल्पिक पहचान का बचाव हासिल नहीं है। राहुल के इस दौर में पार्टी ने कट्टर राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए उदार शांतिवाद की राह चुनी है जो व्यावहारिक नहीं प्रतीत होती है। खासतौर पर यह देखते हुए कि पार्टी खुद भी क्रूर और निर्मम सरकार चला चुकी है। अगर आपको लगता है कि भाजपा के शत्रुओं और गद्दारों के खिलाफ अभियान की काट राजद्रोह विरोधी कानून का खात्मा है तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी लड़ाई किस बात से है।

मोदी और शाह की भाजपा ने न केवल युवा मतदाताओं के मस्तिष्क में उन्मादी राष्ट्रवाद की भावना भरी है बल्कि उसने एक खतरनाक अंधराष्ट्रीयता को जन्म दिया है और इतिहास बताता है कि इसका अंत कभी भला नहीं होता। यहां शत्रु स्पष्ट है और हथियार चिह्नित हैं। पाकिस्तान के लिए हमारे पास जेट विमान और कमांडो हैं और देश के भीतरी दुश्मनों के लिए सोशल मीडिया और लांछन।

कवि प्रदीप ने जिन खतरों और शत्रुओं की पहचान की थी और जिनके बारे में लग रहा था कि हमने उन्हें समाप्त कर दिया है, वे दोबारा जिंदा हो गए हैं और हिंदी मीडिया ने सबसे पहले उस रुझान को भांपा है। साठ वर्ष बाद अब एक नई पीढ़ी और नई शैली (रैप) के कवि ने मौजूदा मिजाज को प्रकट किया है।

रणवीर सिंह- आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म गली ब्वॉय का यह गीत सुनिए: दो हजार अठारह है, देश को खतरा है/ हर तरफ आग है, तुम आग के बीच हो/जोर से चिल्ला दो, सब को डरा दो, अपनी जहरीली बीन बजा के, सबका ध्यान खींच लो। क्योंकि रैपर अपनी बात समाप्त करते हुए कहता है: हम सब अब जिंगोस्तान में रह रहे हैं।

कल्याणकारी एजेंडे को कैसे दिया जाए आकार

नीति नियम

मिहिर शर्मा

देश की राजनीति में व्याप्त कल्याणकारी प्रतिस्पर्धा की आलोचना करना आम बात है। गत वर्ष के अंत में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे। कांग्रेस ने बकाया कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था और उसे चुनाव में जीत मिली थी। मौजूदा आम चुनाव में सत्ताधारी भाजपा को उम्मीद है कि उसने अंतरिम बजट में किसानों को प्रत्यक्ष राशि अंतरण की जो घोषणा की है, उसका उसे फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का ऐलान किया है जिसका दायरा अधिक है मगर उस पर अमल कठिन। राज्यों के दल इस मामले में और उदार रहे हैं। यह बात राजनेताओं की नजर से चूकी नहीं होगी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसे विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत मिली, वह सबसे अधिक कल्याण योजनाएं चलाती है।

प्रतिस्पर्धी कल्याण के खिलाफ दलीलें जगजाहिर हैं। इनके लिए संसाधन जुटाना आसान नहीं और इनकी भरपाई करों के माध्यम से ही होगी या फिर उधार लेकर। यानी यह मुद्रास्फीति को प्रभावित करेगा। प्रत्यक्ष कर अपेक्षाकृत कमजोर है। इसलिए कर में इजाफा करना कठिन है। अगर कर व्यवस्था में सुधार के बिना ऐसा किया गया तो कर वंचना को प्रोत्साहन मिलेगा और पूंजी दूसरी जगह जाएगी। इससे बतौर उत्पादक भारत की स्थिति कमजोर बनी रहेगी। यह बात लंबी अवधि में देश के कामगारों को परेशान करती है क्योंकि कंपनियों की स्थापना नहीं होती। देश का सार्वजनिक ऋण कागज पर अपेक्षाकृत कम है पर देनदारी बढ़ रही है। इससे भविष्य में संकट हो सकता है।

बढ़ता हुआ ऋण निजी निवेश में कमी की वजह बनेगा। इसका असर वृद्धि और रोजगार पर पड़ेगा। ऊंची मुद्रास्फीति भी निवेश को हतोत्साहित करती है। राज्य के स्तर पर प्रतिस्पर्धी लोक कल्याण देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि राज्य इस बात पर सवाल उठाने लगते हैं कि वे केंद्र को कितना पैसा दे रहे हैं और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है और सीधे बाजार तक पहुंच बनाने की राह में क्या बाधा है?

बहरहाल, लोकतांत्रिक राजनीति की अपनी गति होती है। यह समझना भी आवश्यक है कि भारत ने अकारण लोकल्याणकारी युग में प्रवेश नहीं किया है बल्कि समावेशी विकास न कर पाने में विफलता इसकी वजह रही है।

बिना रोजगार वाले विकास को गैर समावेशी वृद्धि करार दिया जा सकता है। यह दिक्कतदेह स्थिति है। ऐसा इसलिए कि रोजगार तलाश करने वालों की फौज राजनेताओं के लिए अहम मतदाता वर्ग है। उनको संतुष्ट करने के लिए सरकार की वेतन बिल बढ़ाते जाने की चाह स्वाभाविक है। आय के सुरक्षित होने और निरंतर बढ़ने के भरोसे के अभाव में मतदाता आगे आकर उनकी आय की रक्षा करे और उसे बढ़ाए। तमाम अध्ययन हैं जो यह दिखाते हैं कि व्यक्तिगत कदम और भविष्य की आय किस प्रकार आर्थिक नीति के संदर्भ में लोगों की राजनीतिक प्राथमिकता में तब्दीली लाते हैं। अगर भारत में मतदाता यह मानते रहे हैं कि मानव पूंजी अथवा महत्त्वाकांक्षा और भविष्य की आय की संभाव्यता के बीच कोई संबंध नहीं है तो फिर वे शायद ही ऐसे रिश्ते पर यकीन करने वाले आर्थिक विचार के पक्ष में मतदान करें। 2019 में कोई राजनेता यह नहीं कहेगा कि जवाबदेह आर्थिक नीति आय सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसलिए कि पिछले एक दशक में दोनों पक्षों को जवाबदेह आर्थिक नीति लागू करने का मौका मिला है और इस पूरी अवधि के दौरान भारत में रोजगार बिल्कुल नहीं बढ़े।

क्या भारत मंदी के चक्र का शिकार है? समावेशी विकास की कमी के कारण लोककल्याण का दबाव बढ़ा है। जबकि यह समावेशी विकास की भविष्य की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में यह गतिरोध बरकरार रहने की संभावना है।

परंतु इससे निकलने की एक राह भी है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हाल के वर्षों में समावेशी विकास की नाकामी को स्वीकार किया जाए। इसके साथ ही मौजूदा राजनीति में लोककल्याण की आवश्यकता को भी समझा जाए। आवश्यकता यह भी है कि कल्याण योजनाओं को समझदारी से तैयार किया जाए। ऐसा करने से भविष्य के लिए मानव संसाधन और आय सुरक्षा तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि कल्याण योजनाओं को ऐसे तैयार किया जाए कि देश की श्रम शक्ति की संभावित उत्पादकता में इजाफा हो सके। इससे बढ़े हुए व्यय के नकारात्मक वृहद आर्थिक प्रभाव को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

यह भी तय नहीं है कि आय समर्थन योजना बेहतर है या नहीं। परंतु कम से कम यह व्यय क्षमता में सुधार लाने का काम करेगी। इससे मानव संसाधन तैयार करने, तलाश की लागत कम करने और श्रम बाजार में समता लाने में भी सहायता मिलेगी।

अगर सरकार स्वास्थ्य एवं मूलभूत शिक्षा पर व्यय बढ़ाएगी तो कहीं अधिक बेहतर होगा। इन नीतिगत प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सरकारी मशीनरी पर भी खर्च किया जाना चाहिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा उत्पादकता बढ़ाएगी। यह काम सस्ती दर पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार को निजी सेवाप्रदाताओं के काम पर करीबी निगाह रखनी होती है अथवा उसे अपने ही स्वास्थ्यकर्मियों को भुगतान करना होता है। प्राथमिक शिक्षा में नतीजों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस दिशा में उचित हल साबित नहीं हुआ और वह दीर्घावधि में कारगर साबित नहीं होगा। वयस्क प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अगर सुधार को लेकर राजनीतिक सहमति के संकेत नहीं नजर आ रहे हैं या जवाबदेह आर्थिक नीति नहीं बनती दिख रही है। हमें यह समझना होगा कि यह बीते दशक में या उससे पहले भी आय में वृद्धि और आय सुरक्षा मुहैया न करा पाने का दुष्परिणाम है। इस नाकामी पर विलाप करने के बजाय अब वक्त आ गया है कि हम यह सवाल उठाएं कि लोककल्याण के एजेंडे को कैसे आकार दिया जाए।

कानाफूसी

वेणुगोपाल पर नजर

कांग्रेस पार्टी में के सी वेणुगोपाल एक ऐसे नेता हैं जिन पर नजर रखने की आवश्यकता है। वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन देश भर में कहां से किसे कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए, इसमें उनकी खूब चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने की एक वजह वेणुगोपाल भी हैं। वह निवर्तमान लोकसभा में अलप्पुजा से सांसद हैं। यह लोकसभा क्षेत्र करीब 100 किलोमीटर की लंबाई में 6 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसका एक हिस्सा कोल्लम जिले में आता है जो मछुआरा समुदाय का केंद्र है। यह वाम धड़े के कई दिग्गज राजनेताओं का जन्मस्थान रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष आपकी सलाह पर आपके राज्य से निर्वाचित होते हैं तो इसके कई फायदे हैं।

दोस्ती-दुश्मनी

राजद प्रमुख लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में उनके बेटे तेजस्वी यादव पर बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इस दौरान उन्हें अपने भाई तेज प्रताप से भी रिश्ते बनाकर रखने हैं जो बागी तेवर दिखा रहे हैं और अगले लालू होने का दम भर रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर दोनों भाइयों की अनबन सामने आ गई। हाल में तेजस्वी ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें दोनों भाई नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में तेज प्रताप के जन्मदिन का केक काटा जा रहा है। उन्होंने अपने भाई तेज प्रताप को टैग करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि तेज प्रताप उन्हें जीवन में अब तक मिले लोगों में सबसे अच्छे हैं। गौरतलब है कि अभी चंद रोज पहले तेज प्रताप ने लालू-राबड़ी मोर्चा बनाने की घोषणा की थी। वह टिकट वितरण में अपनी बात न सुने जाने से नाराज थे।

आपका पक्ष

शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव जरूरी

स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शिक्षा का मतलब केवल विद्यार्थी को जानकारी देना नहीं होता बल्कि एक विद्यार्थी में व्यावहारिक ज्ञान, कुशलता, चरित्र, संवेदना, आत्मविश्वास होना चाहिए जिससे उसके ज्ञान से स्वयं को ही नहीं बल्कि समाज को भी लाभ हो। लेकिन देश की शिक्षा व्यवस्था स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलती नहीं दिखती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक विद्यार्थी का मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर नहीं बल्कि अंकों के आधार पर किया जाता है। शिक्षक जब नैसर्गिक पर्यावरण विषय पढ़ाते हैं तब विद्यार्थी का मूल्यांकन उसके अंकों के आधार पर किया जाता है। आज भी शिक्षा व्यवस्था में विषय को समझाने के बजाए रटवाया जाता है ताकि एक विद्यार्थी को अच्छे अंक मिल सके। इसके लिए मौजूदा पाठ्यक्रम जिम्मेदार हैं। यहां विद्यार्थी विषयों की संकल्पनाएं समझने के बजाए उसे किसी तरह परीक्षा तक याद रखकर पास हो जाता है। मौजूदा पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही है कि अच्छे अंक के सहारे उसे अच्छे विद्यालय में दाखिला मिल जाए और भविष्य में नौकरी लग जाए। जीवनयापन के लिए नौकरी जरूरी है लेकिन व्यावहारिक ज्ञान भी महत्त्वपूर्ण है। इसलिए पाठ्यक्रम के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना जरूरी है। सैद्धांतिक अध्ययन के अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रम को महत्त्व देना चाहिए। बच्चों को रचनात्मक कार्यों में प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल में प्रतिदिन एक पीरियड रखना चाहिए। कौशल शिक्षा का अर्थ और उसका महत्त्व विद्यार्थियों को समझाना चाहिए। योग्य और कुशल शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। खेल को भी महत्त्व देना चाहिए ताकि देश में श्रेष्ठ खिलाड़ी तैयार हों और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। अभिभावकों को भी बच्चों के अंकों के बजाय उनकी समझदारी और कुशलता के आधार पर उनका मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों में अवसाद दूर करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना चाहिए। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी के भीतर की जानकारी के साथ-साथ, भावना, चरित्र, संवेदना, कौशल, व्यावहारिक और रचनात्मक ज्ञान के बीज बोने में सक्षम हो जाती है तो यही विद्यार्थी भविष्य में समाज को छाया देने वाले वृक्ष बन सकते हैं।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल-कॉलेजों में बुनियादी स्तर पर बदलाव करने की जरूरत है

विवादित बयान से बचें नेतागण

हाल में भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा की विवादित टिप्पणी से पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। साध्वी ने मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद पुलिस अधिकारी के संदर्भ में बयान दिया था। विपक्षी दलों ने साध्वी के बयान की कड़ी आलोचना की है। चुनाव आयोग को साध्वी के बयान के खिलाफ शिकायत मिली है तथा आयोग ने मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। दरअसल मुंबई में हुए आतंकी हमले में पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे शहीद हो गए थे। एक शहीद पर साध्वी ने विवादित बयान दे दिया। उनकी चौतरफा आलोचना हुई। अक्सर चुनाव के समय नेताओं के विवादास्पद बयान आते रहे हैं। नेताओं द्वारा आरोप-प्रत्यारोप के दौरान अपनी मर्यादा भूल जाना ठीक नहीं है। नेताओं को वोट पाने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।